क्रमांक	जिले	1991-92	1992-93	1993-94
40.	सरगुजा	258.98	338.40	565.19
41.	रायगढ़	254.28	239.70	394.57
42.	रायपुर	358.98	338.40	554.53
43.	शाहजापुर . . .	119.66	112.80	181.29
44.	उज्जैन	89.75	84.60	138.63
45.	मांडला	239.32	225.60	373.24
	योग :	6865.57	6472.00	10664.00

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन

2426. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत गुजरात के साधनहीन गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलन में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या इस योजना में कतिपय त्रुटियां सरकार के ध्यान में आयी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन त्रुटियों पर काबू पाने हेतु क्या कदम उठाये गए है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम-भाई पटेल) : (क) 31-3-94 की स्थिति के अनुसार वर्ष 1985 के सर्वेक्षण द्वारा पता लगाये गये 4911 समस्याग्रस्त गांवों में से 4902 गांवों में स्वच्छ पेयजल का एक अथवा एक से अधिक जल स्रोत उपलब्ध कराया गया है । शेष 9 समस्याग्रस्त गांवों को 1994-95 के अंत तक कवर कर लिये जाने की संभावना है ।

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत गुजरात के गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नलिखित थीं ।

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1992-93	500 गांव	456 गांव
1993-94	500 गांव	458 गांव
1994-95	1500 बसावटें	68 गांव (6/94 तक)

आठवीं पंचवर्षीय योजना के शेष 2 वर्षों के लिये लक्ष्यों के निर्णय इन वर्षों के लिये निर्धारित परिव्यय के आधार पर लिये जायेंगे ।

(ख) गांवों तक पहुंच न होने तथा सिंचाई प्रयोजन हेतु भूजल की अत्यधिक निकासी के कारण कई क्षेत्रों में जल स्रोतों के सूख जाने की वजह से कवरेज की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है ।

(ग) इन कमियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

—बसावट स्तर तक का ब्यौरा जानने के लिए कार्यक्रम निगरानी प्रणाली संशोधित की गई है ।

—राज्य सरकारों के ग्रामीण जल सप्लाई सचिवों तथा मुख्य अभियंताओं के साथ 2-8-94 को हुई समीक्षा बैठक के दौरान राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे पेयजल सप्लाई के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए भूजल की अत्यधिक निकासी रोकने और नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठायें ।

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सड़कों का निर्माण

2427. **जौधरी हरमोहन सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कुल कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है ;

(ख) इस कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ग) इस संबंध में जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है । उसके अनुसार जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य में वर्ष 1993-94 तक 1,30,310.32 किलोमीटर लम्बी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया जिन पर 76467.58 लाख रुपये खर्च हुए ।

(ग) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण के जिलेवार ब्यौरे केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जाते हैं ।

Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission

2428. *SHRI GOVINDRAO ADIK:* Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the outlay for the year 1993-94 under Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission and the amount that has been released upto December, 1993;

(b) the total number of problem villages which were to be covered under this programme and how many out of these have actually been covered in the year 1993-94;

(c) the action plan for the year 1994-95 and how much amount has been set apart for completion of this work in the current financial year;

(d) whether Government is satisfied with the progress made in this direction in the year 1993-94; if not, the reasons therefor; and

(e) the remedial measures Government propose to take to cover the maximum number of beneficiaries during 1994-95?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) The outlay for the year 1993-94 under Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission was Rs. 740.00 crore and an amount of Rs. 447.63 crore was released upto December, 1993.

(b) Against a target of 750 problem villages (including 25 Uninhabited villages), 447 problem villages were covered during 1993-94.

(c) A target of coverage of 77770 habitations has been set for the year 1994-95 for which an outlay of Rs. 800 crore has been provided.

(d) Due to non-utilisation of funds in J and K, inaccessibility of hard